



डॉ० सरोज यादव

## सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष में वर्तमान उच्च शिक्षा का भावी पथ

एसो0 प्रोफेसर- बी0एड0 चरण सिंह पी0जी0 कालेज, हेओरा, इटावा, (उ0प्र0), भारत

Received- 10.12. 2021, Revised- 15.12. 2021, Accepted - 19.12.2021 E-mail: drsrjyadav@gmail.com

**सारांश:** सभी प्राणियों को अपने जन्म-जन्मान्तर अपनी परिस्थिति के अनुकूल कर्म करना पड़ता है, इसी प्रकार के कर्मों के निमित्त मानव-प्राणी को भी सीखना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, जिसे वह संचित करता है, इस दृष्टि से मनुष्य जीवन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव जीवन के उदय से लेकर आज तक शिक्षा ने विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया को सतत् रूप प्रदान किया है। विश्व के सभी देशों ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए अपनी शैक्षिक प्रणाली को विकसित किया है और समय-समय पर उसमें संशोधन एवं विभिन्न स्तरों पर सुधार किया है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके द्वारा अपने भावी नागरिकों को दी जाने वाली शिक्षा तथा संस्कारों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है, जो राष्ट्र अपनी भावी पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराता है। तथा उसे उच्च संस्कारों एवं आदर्शों से परिपूर्ण करता है, उसे त्याग और परहित के लिए तत्पर रहना सिखाता है, वह राष्ट्र प्रगति के उच्चतम शिखर पर आसीन होता है तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित करता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव जीवन अधिक क्लिष्ट है, जीवन जीने के लिए दूसरे प्राणियों की तरह मनुष्य को मात्र दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे मानसिक आवश्यकताओं (क्षुधा) को भी शान्त करना होता है। मानव जीवन में शिक्षा की महत्ता को दर्शाते हुए जॉन मिन्टन ने लिखा-“मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसी को कहता हूँ जो किसी व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वह निजी सार्वजनिक तथा शान्ति व युद्ध कालीन कार्यों को दक्षता, सुन्दरता व न्यायोचित ढंग से कर सके।”

### कुंजीशब्द- जन्म-जन्मान्तर, अनुकूल कर्म, मानव-प्राणी, सामाजिक सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रणाली, उदार शिक्षा।

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, तथा विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में दी जाती है। उच्च शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक पहलू है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक सुसंस्कृत व सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। राधा कृष्णन कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों को सभ्यता का अंग कहा है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को राष्ट्र निर्माण का कार्य करना है। आज के भारत का निर्माण उसके विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रारूप पर निर्भर करता है।

वर्तमान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन तथा समाज व राष्ट्र के विकास के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम तैयार करती है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों में शारीरिक श्रम और ग्रामीण जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। स्तर के आधार पर उच्च शिक्षा को चार भागों में बाटा गया है-

1. स्नातक
2. स्नातकोत्तर
3. अनुसंधान
4. डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र

वर्तमान में स्तरानुसार-स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान तथा डिप्लोमा स्तरों पर अध्ययनरत् छात्रों का लगभग अनुपात क्रमशः 76-5:11-7:10:10-9 का है यह अनुपात प्रदर्शित करता है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं में स्नातक की शिक्षा के उपरान्त बहुसंख्यक विद्यार्थी अध्ययन से वंचित हो जाते हैं बजह चाहे संसाधन की कमी या व्यक्तिगत/पारिवारिक अक्षमता हो। ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए स्नातक शिक्षा, शिक्षा जीवन का अन्तिम पड़ाव होता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्नातक स्तर पर छात्र संख्या (अनुमानित) तालिका में प्रदर्शित है-

### स्नातक स्तर पर छात्रों का नामांकन (अनुमानित)

सत्र	विश्वविद्यालय		महाविद्यालय		दूरस्था शिक्षा		शिक्षा		कुल	
	छात्र संख्या	%	छात्र संख्या	%	छात्र संख्या	%	छात्र संख्या	%	छात्र संख्या	%
2000-01	-	-	-	-	-	-	-	-	8400000	-
2005-06	15 लक्षा	14.6%	66 लक्षा	64.1%	22 लक्षा	21.4%	-	-	1 करोड 3 लक्षा	-
2010-11	-	-	-	-	-	-	-	-	15 करोड (न ग भग)	-
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-	25 करोड (न ग भग)	-



तालिका के आकड़ों यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछले 10 वर्षों में स्नातक स्तर की शिक्षा में छात्रों के दाखिला में संख्यात्मक वृद्धि हुई है परन्तु केवल संख्या बढ़ाकर हम शिक्षा के विकास की गाथा नहीं सुना सकते हैं, इसके लिए हमें इसमें गुणात्मक सुधार करनी होगी।

मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। जावड़ेकर के मंतव्य का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्किल इंडिया योजना का आधार ही उच्च शिक्षा है। यूनिवर्सिटी में सुधार किए बिना युवाओं को आधुनिक स्किल देना लगभग असंभव है। लेकिन देश की उच्च शिक्षा का रोग असाध्य हो गया है। अब जवाबदेही स्थापित करने जैसे छुटपुट कदमों से बात नहीं बनेगी। सर्जरी की जरूरत है। समस्या की जड़े सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी में राजनीतिक नियुक्ति वाइस चांसलरों द्वारा यूनिवर्सिटी के कामकाज में रूचि नहीं ली जाती है। आज आइआईटी में भी छात्र सेल्फ स्टडी अधिक कर रहे हैं। प्रोफेसर पूर्वनिर्मित स्लाइड शो दिखाकर चले जाते हैं। विद्यार्थियों के संदेहों को दूर करना उनके एजेंडे में नहीं है। इस विकट स्थिति में प्रोफेसरों की जवाबदेही को प्रभावी ढंग से स्थापित करना लोहे के चने चबाना है। जावड़ेकर यदि सच्चे मायने में जवाबदेही स्थापित करेंगे तो शिक्षक माफिया सामने खड़े हो जाएंगे। राजीतिक नियुक्तियां न करने से भी अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूनियन द्वारा प्रोफेशनल वाइस चांसलर को असफल कर दिया जाएगा। इस विकट परिस्थिति की जड़ प्रोफेसरों को स्थाई नौकरी देने में है।

अमेरिका में उन सरकारी कालेजों को अतिरिक्त धन एव सुविधाएं दी जाती हैं जहां प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है तथा जहां प्रोफेसर ठेके पर रखे गए हैं। इस प्रणाली को जावड़ेकर को लागू करना चाहिए। नए प्रोफेसरों की नियुक्ति को अनिवार्यतः ठेके पर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाए।

वर्तमान यूनिवर्सिटी व्यवस्था अस्ताचल की ओर बढ़ रही है। प्राचीन काल से अब तक शिक्षण का मूल स्वरूप गुरु-शिष्य परंपरा का था। विद्यार्थियों के सामने प्रोफेसर खड़े होकर लेक्चर देते थे। इंटरनेट ने इस परंपरा पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वर्तमान में प्रोफेसरों द्वारा अपने ज्ञान को ऑनलाइन प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। विद्यार्थी अपने लिए अनुकूल समय में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर साटवेयर से शिक्षा प्राप्त करता है। जरूरत के अनुसार यदा कदा ट्यूटोरियल चलाए जाते हैं जहां विद्यार्थियों द्वारा अपने संदेहों को दूर किया जाता है। पूर्व में एक प्रोफेसर द्वारा निर्मित साटवेयर से एक लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन तथा लेक्चर द्वारा शिक्षण की प्रथाओं का मिला-जुला मॉडल बन रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा एक ही प्रोफेसर हजारों विद्यार्थियों को एक साथ ऑनलाइन लेक्चर दे सकता है। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से संदेह दूर किया जा सकता है। यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि विद्यार्थी अपने संदेह को वेबसाइट पर डाले तथा प्रोफेसर उसका निवारण विशेष समय एवं दिन को करें ताकि तमाम विद्यार्थी उसका लाभ उड़ा सके। इस प्रथा का विस्तार होगा इसमें संदेह नहीं है। तथा ऑनलाइन उच्च शिक्षा से शिक्षा लागत में भारी गिरावट आयेगी। ऑनलाइन कोर्स को अपना लेने से हमारी युनिवर्सिटी व्यवस्था में प्रोफेसरों की भारी भरकम फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अतः जावड़ेकर को चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे। प्रोफेसरों की पदोन्नत को ऑनलाइन कोर्स बनाने से जोड़ दिया जाये और महत्वपूर्ण कदम विदेशी युनिवर्सिटियों को प्रवेश देने का उठाना चाहिए। इनके प्रवेश से भारतीय युनिवर्सिटियों को मजबूरन अपनी गुणवत्ता में सूधार लाना होगा। परन्तु यह सब तभी सम्भव होगा जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाये तब निश्चित रूप से भारत में उच्च शिक्षा की जो तस्वीर सामने आयेगी विश्व के पटल पर उसकी एक अलग पहचान होगी।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता डॉ0एस0पी0-भारत में शिक्षा प्राणाली का विकास, शारदा पुस्तक भवन।
2. बुच एम0बी0-सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बड़ौदा।
3. विश्वविद्यालय आयोग (1948-49).
4. शिक्षा आयोग (1964-66).
5. हिन्दुस्तान समाचार पत्र - संस्करण गोरखपुर।
6. दैनिक जागरण समाचार पत्र -संस्करण गोरखपुर।

\*\*\*\*\*